

पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह समेत दो के खिलाफ चार्जशीट, लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। पूर्व सांसद प्रयागराज

मय चालक हिरासत में ले लिया गया। पिर आशयक कार्रवाई के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मामले में चालक व 50 अज्ञात समर्थकों

बाद उन्हें धारा 149 की पर्यायक विवरिति उल्लंघन रमण के पहुंचने पर उन्हें आशयक कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया। उधर, सपा प्रदेश कार्यालय लखनऊ में निर्वाचन कार्य देख रहे केके श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने घटना के संबंध में प्रदेश के मुख्य निवाचन अधिकारी से बात की है। रिपोर्ट करेली थाने के दरोगा मनीष कुमार राय की तहार पर दर्ज की गई। इसमें बताया कि मतदान के दौरान स्वतन्त्र प्राप्त हुई कि रेवती रमण सिंह वाहन में गनर के साथ आकर मतदान केंद्र लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र के सामने रुके हैं। समर्थकों को अपने प्रत्याएक के पक्ष में बोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मौके पर पहुंचने पर देखा कि वहाँ काकी भीड़ लगी थी। रेवती रमण फॉर्म्यूलर कार में चालक चंद्रशेखर व दो गनर संग बैठे थे वाहन पास मांगने पर चालक ने जिला निवाचन प्रयागराज का सात मई को निर्गत वाहन प्राप्त किया जास्तीमें 23 मई 2024 की शाम पांच बजे तक अनुमति अंकित है। निर्देश के विपरीत पास वाहन के शीशे पर भी चस्पा नहीं था।

है। वह शनिवार शाम चार बजे के करीब अचानक करेली के 60 फीट रोड पर स्थित राजस्व प्रशिक्षण मतदान केंद्र के पास पहुंच गए। उनके पहुंचते ही वहाँ समर्थकों की भीड़ जुट गई। करेली में शनिवार को गठनथन प्रत्याशी के पिता व पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह के केंद्र के बाहर पहुंचने पर हांगामा हो गया। सरकारी काम में बहार पहुंचने, आचार संहिता उल्लंघन के साथ चुनाव प्रभावित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उन्हें

मनी लांडिंग केस में माफिया अतीक की पत्री शाइस्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड

में फरार चल रही 50 हजार की इनामी शाइस्ता परवीन की प्राप्ति।

इसके लेकर प्रवर्तन निवाशलय ईडी की टीम छानबीन में जुट गई है। पुलिस की ओर से कुर्क संपत्तियों की जानकारी ली जा रही है और अतीक व उसके परिवार के सदस्यों के नाम की चल-अचल प्राप्ती को चिह्नित किया जा रही है। अतीक अहमद और उसके परिवार के सदस्यों के नाम की चल-अचल संपत्ति को चिह्नित किया जा रहा है। हालांकि मनी लांडिंग केस में ईडी द्वारा अभी तक आठ करोड़

की ओर से चिह्नित भी है। अतीक अहमद और उसके परिवार के सदस्यों की जानकारी ली जा रही है। अतीक अहमद और उसके परिवार के सदस्यों के नाम की चल-अचल संपत्ति को चिह्नित किया जा रहा है। हालांकि मनी लांडिंग केस में ईडी द्वारा अभी तक आठ करोड़

आधुनिक गेट हाउस

- वाटर प्रूफ शेड
- पार्किंग की सुविधा
- मन्दिर की सुविधा
- सी.सी.टी.वी.
- छोटे-बड़े कार्यक्रमों के अलग-अलग रेट
- 45000 sq. feet. एरिया
- हरे-भरे वातावरण
- AC कमरा (VIP)

CALL: 9519313894, 9415608783, 9415608710

आधुनिक समाचार पब्लिशिंग हाउस, यूपीएसआईडीसी, रेमण्ड रोड, औद्योगिक थाने के पीछे भारत पेट्रोलियम के पहले, औद्योगिक क्षेत्र, नैनी, प्रयागराज

सफाई मशीन चोरी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, सपा नेता आजम खां पर दर्ज है केस

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। जौहर यूनिवर्सिटी में नार पालिका की सफाई में शीशन

मामले में कोर्ट अपना फैसला

मामला हाईकोर्ट की लिस्टिंग में

एसटीएफ की गिरफ्त में आए एक-एक लाख के इनामी बदमाश अब्दुल मजीद और सुहेल, रच रहे थे साजिश

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। करीब 15 महीने से फरारी काटने वाले एक-एक लाख की गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने

मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद आरोपित घर छोड़कर फरार हो गए। तब पूलिस ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया।



मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनायी। जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की सफाई की मशीन बरामद होने सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी में नार पालिका की मशीन बरामद होने के मामले में रामपुर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रामपुर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रामपुर कोर्ट के फैसले को आजम खां और अब्दुला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत याचिका दाखिल की है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में सफाई मशीन बरामद होने के मामले में फैसले सूची के पूर्व केनिंगटन मंत्री और विरिट एसपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रामपुर कोर्ट के फैसले को आजम खां और अब्दुला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत याचिका दाखिल की है।

जमानत याचिका दाखिल की है।

अखिलेश-ओवैसी के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका पर बहस पूरी, आदेश 17 सितंबर को

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। जानवापी को लेकर

पांडेय की ओर से सुप्रीम कोर्ट

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) कारण आयोग से जुड़े सभी

नीतिगत नियन्य अटक हुए थे। अभ्याधिकारी का मानना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय

पांडेय की ओर से अधिकारी को लेकर के अधिवक्ता रवि प्रकाश शुक्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और असुहीन ओवैसी का बयान हेट स्पीच की श्रृंगी में आता है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की नजीरों का जिक्र किया।

पांडेय की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रवि प्रकाश शुक्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव व प्रपुत्र असुहीन ओवैसी और अन्य के खिलाफ अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार की अदालत में लंबित पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को बहस पूरी हो गई। याचिकार्ता हरीशंकर

पांडेय की ओर से चुनौती देते हुए बहस शिक्षा विभाग में आयोग से जुड़ी हुई है। ऐसे में वह शिक्षा विभाग में भर्तीयों को परी गंभीरता से लेंगी और नियुक्ति के बाद जल्द ही लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित करेंगी।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को घटला स्थायी अध्यक्ष मिलने के

बाद दो साल से लंबित पड़ी भर्तीयों

को रफतार मिली। वहीं, दो साल से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तीयों को परी गंभीरता से लेंगी और नियुक्ति के बाद जल्द ही लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित करेंगी। अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के

गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रो. कीर्ति पांडेय खुद शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। ऐसे में वह शिक्षा विभाग में भर्तीयों को परी गंभीरता से लेंगी और नियुक्ति के बाद जल्द ही लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित करेंगी। अध्यक्षीयों ने दोनों भर्तीयों की परीक्षा तिथियां घोषित किया जाने की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधिक बढ़ा दर्शाया। प्रदेशीय अध्यक्षीयों ने दोनों भर्तीयों की परीक्षा तिथियां घोषित किया जाना चाहिए।

अध्यक्षीयों ने दोनों भर्तीयों की परीक्षा तिथियां घोषित किया जाने की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधिक बढ़ा दर्शाया। प्रदेशीय अध्यक्षीयों ने दोनों भर्तीयों की परीक्षा तिथियां घोषित किया जाना चाहिए।

अध्यक्षीयों ने दोनों भर्तीयों की परीक्षा तिथियां घोषित किया जाने की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधिक बढ़ा दर्शाया। प्रदेशीय अध्यक्षीयों ने दोनों भर्तीयों की परीक्षा तिथियां घोषित किया जाना चाहिए।

अध्यक्षीयों ने दोनों भर्तीयों की परीक्षा तिथियां घोषित किया जाने की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधिक बढ़ा दर्शाया। प्रदेशीय अध्यक्षीयों ने दोनों भर्तीयों की परीक्षा तिथियां घोषित किया जाना चाहिए।

अध्यक्षीयों ने दोनों भर्तीयों की परीक्षा तिथियां घोषित किया जाने की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधिक बढ़ा दर्शाया। प्रदेशीय अध्यक्षीयों ने दोनों भर्तीयों की परीक्षा तिथियां घोषित किया जाना चाहिए।

अध्यक्षीयों ने दोनों भर्तीयों की परीक्षा तिथियां घोषित किया जाने की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधिक बढ़ा दर्शाया। प्रदेशीय अ

सम्पादकीय

यह असंवेदनशीलता नई नर्ही
पुलिस के दमन से हताशा,
जागृति के साथ सड़कों पर
भैं

आक्राशत जनता ले दिनों जो दश्य में समता ने?

बंगाल में प्रभुता दिनों ता दृश्य दिखे, वे बहुत दिनों से सुलग रहे क्षेभ के ज्वालामुखी बनने की कहानी है। पश्चिम बंगाल में 27 अगस्त के नवानन् अधियान को लेकर एक बांगा गीत वायरल हुआ है, जो राज्य के मौजूदा हालात को बखूबी बयां करता है। 'ए केमन राज्य बलो, के खराब आर के भालो। ए केमन होच्छे खेला, चारो दिगे कष्टेर मेला। भालो मानुष अंधकारे, अमानुषरा आलोर डारे' यानी यह कैसा राज्य है, कौन अच्छा है और कौन खराब-भेद करना मुश्किल है। यह किस तरह का 'खेल' है? हर तरफ दुख-दर्द का मेला है। अच्छे लोग अंधकार में रह रहे हैं और अमानुष प्रकाश का आनंद उठा रहे हैं। बंगाल के इस कानफोड़ा कोलाहल और बीच-बीच में उठ रहे आर्तनाद के पीछे 'अब बस, बहुत हुआ' जैसा क्षोभ है। पुलिस को दमन की मशीनरी बनाने और भ्रष्टाचार व गुण्डागर्दी को प्रतिष्ठानिक रूप देने के चलते आम जनता हताश है। आरजी कर अस्पताल की डॉक्टर से दुर्क्षम व हत्याकांड ने आक्रोश को ज्वालामुखी बना दिया है।

छात्र समाज के नवानन्द चलो अभियान को सत्ताधारियों ने भले ही 19 जगहों पर किलानुमा दीवारें खड़ी कर विफल कर दिया हो, पर 28 अगस्त को बुलाए गए बंगाल बंद को विफल करने के लिए उत्तरी पुलिस को कड़े प्रतिरोध करा सामना करना पड़ा। ‘आत्महत्या’ (जैसा कि फोन कर अस्पताल ने बताया) करने वाली अपनी इकलौती बेटी का शव देखने के लिए मां-बाप को अगर तीन घंटे का इंतजार कराया गया, तो शक क्यों नहीं पैदा होगा सवाल है कि जिस नवानन्द अभियान को रोकने के लिए अगर 19 जगहों पर लोहे की दीवारें खड़ी की गई थीं, तो 14 अगस्त की रात पुलिस कहाँ थी? जब उपद्रवियों ने अस्पताल की करोड़ों की संपत्ति तोड़ दी संदेशखाली कांड में शेष शाहजहां को पकड़ने में 50 दिन लगाने वाली पुलिस की मौजूदा सक्रियता सवालों के घेरे में है सवाल है कि आरजी कर मामले में मुख्यमंत्री ममता ने खुद के शासन के खिलाफ पदयात्रा का प्रहसन क्यों किया उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा थारा, जिसका जवाब आया कि पश्चिम बंगाल को दुष्कर्म और बाल यौन अपराध के मामलों की सुनगाई के लिए 123 फास्ट-ट्रैक अदालतें आवंटित की गई हैं, लेकिन उनमें से कई अदालतें आज भी काम नहीं कर रही हैं। 28 अगस्त को तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस की भाषण

द जूकीपर्स वाइफ नाजीकाल का मानवीय चेहरा

यह सोच-समझ कर एक रणनीति के तहत किया था। सूरांगों का खाली इकट्ठा करने के बहाने घेटो में जावा संग में छिपा कर यहौदियों को आते हैं। ये यहौदियों को भेष बदल

A photograph showing a row of books on a dark wooden shelf. The books are of various colors, including red, blue, green, and yellow, and are standing upright.

A photograph showing a stack of approximately ten books on a wooden shelf. The books are of various thicknesses and colors, including shades of brown, tan, and white. In the background, more bookshelves filled with books are visible, though they are slightly out of focus.

कूरता का शिकार बनता है। लूट-पाट, हत्या, लोगों को उठाकर ले जाना आम घटनाएँ हन् जाती हैं। कर सीमा पार करा देते हैं, कुछ नागरिकता दिलवा देते हैं। अब उन घर और चिडियाखाना दो तरह

जाना जाना जाना देखना बैरांगा हाँ
हाँहदियों के लिए पीला डेविट का
स्टार बांह पर लगाना अनिवार्य है।
यहदी हघों के भीतर भी सुरक्षित
नहीं है। जनिक्की के दो चित्र

नहां हा जाबास्का क दा अंत्र दूसरों के लिए इन पति-पत्नी से बचाव की गुहार लगाते हैं। जान बचाने के लिए वे मागदा को अपनी परछती में छुपाते हैं, लेकिन यही उनकी दया-ममता रुक्ती नहीं है।

जागीर दोनों मनाव रखता है। हाँ यह जाबिन्स्की दम्पति लुज हेक के समक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं, वे सूअर पालन करेंगे जो अधिकृत करने वाली सेना के भोजन के काम आएंगे। प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, वार्सा का नामी-

भारतीय न्याय प्रणाली: अब राष्ट्रीय न्यायिक सेवा के गठन का वक्तु प्रतिभाशाली न्यायाधीशों को मिलेंगे बेहतर अवसर

जला अदालता के राष्ट्रीय सम्मेलन में लंबित मुकदमों के बोझ पर चिंता जाहिर की गई और प्रधान न्यायाधीश ने जजों की राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया की पैरवी की। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से प्रतिभावान न्यायाधीशों को ऐसा विकल्प उपलब्ध होगा, जो इस संस्था की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयां दे सकता है। लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या पर एक बार फिर गंभीर चिंता व्यक्त

गया है, जब क्षेत्रवाद आर राज्य केंद्रित चयन की संकीर्ण सीमाओं से आगे बढ़ा जाए। पहले भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सुझाव आते रहे हैं। विधि आयोग वर्ष 1958 और वर्ष 1978 में दो अलग-अलग संस्कृतियों के माध्यम से इसके लिए सुझाव दे चुका है। आयोग का मत था कि इससे अदालतों में लंबित मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण में आसानी होगी, न्यायिक-संरचना

सुझाव और निर्देश दिया था। सबसे पहले वर्ष 1992 में 'ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन' बनाम भारत संघ' में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था। उसके बाद फिर वर्ष 1993 में इस पर जरूरी पहल करने की जिम्मेदारी सरकार के विवेक पर छोड़ दी गई। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय का स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए उसके प्रति सम्मान ही उसका ताकत की गंगत्री होती है। इसलिए उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सजग रहने की जरूरत होती है। मुकदमों का अंबार, उनके निस्तारण में देरी तथा पारदर्शिता से जुड़ी अपेक्षाकृत न्यायपालिका की साख को सबसे अधिक प्रभावित कर रही है। पारदर्शिता के प्रति आग्रही समाज में गैर-जरूरी गोपनीयता कई बार अविश्वास के काल्पनिक कारणों तथा आधारों को तैयार करने की

दश के लिए एक ऐसा पारदर्शी चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रतिभाशाली युवाओं को मौका मिलेगा। इसमें समाज के सभी वर्गों तथा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। चूंकि यह चयन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, इसलिए इसमें सबसे अच्छे लोगों के चयन की एक परंपरा विकसित होगी। मुकदमों की बढ़ती संख्या का एक कारण यह भी है कि हमारे यहां न्यायाधीशों की बहुत कमी

वतमान दर के मुताबिक 2040 कुल 15 करोड़ मुकदमे लिंबित होंगे, जिनके निस्तारण के लिए 1,000 न्यायाधीशों की जरूरत होगी। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जूदा कार्य पद्धति को देखते हुए यह संभव नहीं लगता। खेल भारतीय न्यायिक सेवा गठन से इस चुनौती से निपटना सान हो जाएगा, संविधान के नुच्छेद 312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में कहा गा है कि इसके द्वारा चयनित



सम्मेलन में राष्ट्रपति द्वारा मुर्मूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड तथा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक स्वर में शीघ्र और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड ने न्यायिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया की पैरवी करते हुए कहा कि अब समय आ जाहा और उक्त फारमान पर्याप्त मुकदमों का तेजी से निपटारा होगा और आम लोगों का उन पर भरोसा बढ़ेगा। संसद की 'लोक शिकायत, कानून तथा न्याय की स्थायी समिति' ने भी वर्ष 2006 में इसके विषय पर सुझाव दिया था। इसके अलावा, इस समिति ने एक मसीदाम भी तैयार किया था, किंतु वह आगे नहीं बढ़ पाया। सर्वीच्च न्यायालय ने भी कई मौके पर इस संबंध में

ब्यूरोप या नामांकित कर्तव्य
अब उन पर भी प्रश्न उठने लगे
हैं। उच्च न्यायालय और सर्वीक्षण
न्यायालय वें कुछ वर्तमान-
न्यायाधीशों ने भी उस पर सवाल
उठाए हैं। ये सभी तथ्य ऐसे हैं
जो अखिल भारतीय न्यायिक
सेवाओं के पक्ष में पर्याप्त आधार
तैयार करते हैं। न्यायपालिका के
अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में
यह कहा जा रहा है कि यह पूरे

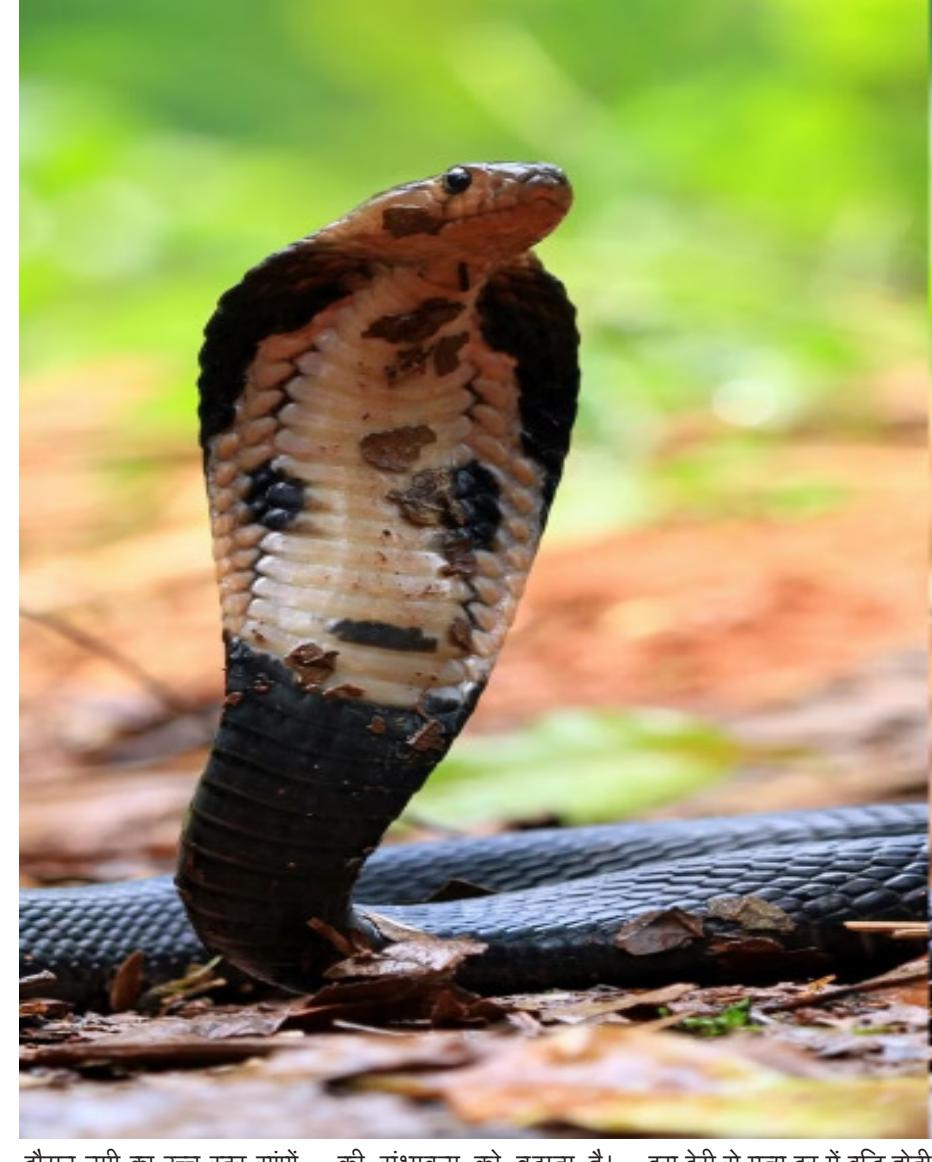
वर्ही हमारे यहां इतनी आबादी पर मात्र 21 न्यायाधीशों के पद ही सृजित हैं। अलग-अलग राज्यों में उनके चयन की प्रक्रिया में अक्सर देरी होती रहती है, जिसके कारण कुल 25,246 स्वीकृत पदों के सापेक्ष केवल 19,858 न्यायाधीश ही कार्य कर रहे हैं। नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार, मुकदमों के दायर होने

केंद्रीय स्वास्थ्य जांच ब्यूरो की सिपोर्ट (2016-2020) के अनुसार पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्कॉलर्स संगठन और नेशनल मलबे के नीचे शरण लिए हुए होते हैं। माना जाता है कि मॉन्सरू के सम्पर्क विशेष रूप से ग्रामीण और शर्ष-आड़ी क्षेत्रों में सांप के काटने सहायता और एंटीवेनम तक पहुंच सीमित दौरे के कारण उपचार में चाहिये कि सांप मूलतः हमारा शान्त नहीं है। वह बिना ऐसे हमला नहीं

ट्रॉप (2015-2020) के अनुसार, भारत में सर्पदंश के मामलों की औसत वार्षिक आवृत्ति (फ्रीकरेसी) लगभग 3 लाख है और लगभग 2000 मौतें सर्पदंश के कारण होती हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भारत में सर्पदंश से होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या किसी के पास नहीं है, सांप को देखते ही शरीर में सिंहरन दौड़ पड़ती है। मनुष्य की इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया से समझा जा सकता है कि अधिक झाड़ियों, घास में और बिल में दुबका हुआ सांप कितना खतरनाक होता है। बरसात के इन दिनों में धान आदि की खेती का मौसम है और यही समय सर्पदंश के लिए सर्तांशिक जोखिमपूर्ण है। ट्रॉपसल

जब हाहरा द्यात्रा न, राय के काट-

राष्ट्रीय हानि के कारण उपचार में



दारान नमा का उच्च स्तर सापा को अधिक सक्रिय बना सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्म, गीली परिस्थितियों में शिकार की उपलब्धता बढ़ सकती है, जिससे सांपों की अधिक गतिविधि हो जाती है। भारत की जनसभ्या बढ़ते जाने के साथ ही अन्य मानव-जीव संघर्ष की तरह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मानव-सांप संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है। मानव निवास स्थितार प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण करता है। लोगों

ज
वि
न
स
क
स
व
है
क
क
व
3
ब
ति

